



नेट न्यूट्रैलिटि

प्रलिस के लयि:

सेलयुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI), भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकरण (TRAI), इंटरनेट सेवा प्रदाता ।

मेन्स के लयि:

नेट न्यूट्रैलिटि ।

चर्चा में क्यों?

[सेलयुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया \(COAI\)](#), जो भारत में तीन प्रमुख [दूरसंचार ऑपरेटर](#) - भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रलियंस जयि का प्रतिनिधित्व करता है, ने मांग की है कि [यूट्यूब तथा व्हाट्सएप](#) जैसे प्लेटफॉर्म नेटवर्क लागत को पूरा करने हेतु राजस्व का एक हिस्सा भुगतान करें ।

- इसने [नेट न्यूट्रैलिटि](#) के संदर्भ में चर्चा को फरि से शुरू कर दिया है ।

इस मुद्दे के संदर्भ में तर्क और हालिया घटनाक्रम:

- [दूरसंचार ऑपरेटर](#) उनके नेटवर्क के व्यापक उपयोग के लयि भुगतान की मांग कर रहे हैं ।
 - [यूरोपीय संघ](#) में [दूरसंचार ऑपरेटर](#) भी वषियवस्तु प्रदाताओं से समान उपयोग शुल्क की मांग कर रहे हैं ।
 - वषियवस्तु प्रदाताओं का तर्क है कि सीमति संख्या में बड़े अभिकर्त्ताओं पर भी इस तरह कशुल्क लगाना, [इंटरनेट के स्वरूप का वरूपण](#) है ।
- वर्ष 2016 में [भारतीय दूरसंचार नयामक प्राधकरण \(Telecom Regulatory Authority of India- TRAI\)](#) ने [नेट न्यूट्रैलिटि](#) के पक्ष में फैसला सुनाया ।
- वर्ष 2018 में [दूरसंचार वभाग](#) ने [एकीकृत लाइसेंस](#) में नेट न्यूट्रैलिटि अवधारणा को स्थापति कयि, जसिकी शर्तों से सभी दूरसंचार ऑपरेटर और इंटरनेट प्रदाता बाध्य हैं ।

नेट न्यूट्रैलिटि

- नेट न्यूट्रैलिटि [सदिधांत के अनुसार](#), सभी इंटरनेट ट्रैफिकि के साथ बना कसि भेदभाव या कसि वशेष वेबसाइट , सेवा या ऐप को प्राथमकित्ता दयि बना समान व्यवहार कयि जाना चाहयि ।
- नेट न्यूट्रैलिटि यह सुनिश्चति करती है कि [इंटरनेट पर सूचना और सेवाओं तक सभी की समान पहुँच हो](#), भले ही उनके वत्तीय संसाधन या उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली वेबसाइट्स का आकार और शक्तकुछ भी हो ।
 - यह एक महत्त्वपूर्ण सदिधांत है जो इंटरनेट पर एक [समान अवसर सुनिश्चति](#) करने में मदद करता है तथा [सूचना और वचारों के मुक्त प्रवाह की रक्षा](#) करता है ।
- नेट न्यूट्रैलिटि के बना [इंटरनेट सेवा प्रदाता](#) उपयोगकर्त्ताओं को कुछ वेबसाइट्स और सेवाओं की ओर ले जाने या दूसरों तक पहुँच को सीमति करने के लयि संभावति रूप से अपनी बाज़ार शक्तिका उपयोग कर सकते हैं ।

A QUICK REMINDER

What is net neutrality?

All traffic on the internet should be treated equally.

NO BLOCKING

Your internet access provider (IAP) cannot block you from accessing legal content of your choice.

NO THROTTLING

Your IAP cannot intentionally throttle legal internet traffic to slower speeds than other traffic.

NO PAID PRIORITIZATION

Your IAP cannot sell 'fast lane' service to content providers who can pay more than others.



इंटरनेट क्षेत्र में वभिन्न हतिधारक:

- इंटरनेट क्षेत्र में वभिन्न हतिधारक हैं:
 - किसी भी इंटरनेट सेवा के उपभोक्ता ।
 - दूरसंचार सेवा प्रदाता (TSP) या इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) ।
 - ओवर-द-टॉप (OTT) सेवा प्रदाता (जो वेबसाइट और ऐप जैसी इंटरनेट एक्सेस सेवाएँ प्रदान करते हैं) ।
 - सरकार, जो इंटरनेट कंपनियों के बीच संबंधों को वनियमिति और परभाषति कर सकती है ।
 - इसके अलावा **TRAI दूरसंचार क्षेत्र में एक स्वतंत्र नयामक है**, जो मुख्य रूप से TSP और उनकी लाइसेंसिंग शर्तों आदि को नयित्ति करता है ।

नेट न्यूट्रैलिटी का वनियमन:

- अब तक नेट न्यूट्रैलिटी को भारत में किसी भी कानून या नीति ढाँचे द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वनियमिति नहीं कयि गया है ।
- पछिले वर्षों के दौरान नेट न्यूट्रैलिटी से संबंधित नीति निर्माण में कुछ वकिस हुआ है ।
 - ट्राई डेटा सेवाओं के लयि अलग-अलग मूल्य निर्धारण के साथ-साथ ओवर-द-टॉप सेवाओं (OTT) हेतु नयामक ढाँचे पर काम कर रहा है ।
 - दूरसंचार वभाग द्वारा गठित एक समिति ने भी नेट न्यूट्रैलिटी के मुद्दे की जाँच की है ।
- इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्राज़ील, चिली, नॉर्वे, आदि जैसे देशों में कुछ प्रकार के कानून, व्यवस्था अथवा नयामक ढाँचे हैं जो नेट न्यूट्रैलिटी को प्रभावति करते हैं ।

नेट न्यूट्रैलिटी नहीं होने की स्थिति के परिणाम:

- इंटरनेट संबंधी एकाधिकार:
 - ISP इससे अधिक लाभ प्राप्त करने के लयि नेट न्यूट्रैलिटी के बनिा इंटरनेट ट्रैफिक को संशोधति करने में सक्षम होंगे ।
 - इससे उन्हें सामान्य वेबसाइट की तुलना में अधिक बैंडवड्थि की खपत करने वाले YouTube और Netflix जैसी कंपनियों को सेवाओं के लयि चार्ज करने की शक्ति मिलेगी ।
- हतोत्साहति नवाचार:
 - नेट न्यूट्रैलिटी की कमी वेब/इंटरनेट पर नवाचार को काफी हतोत्साहति कर सकती है । त्वरति पहुँच के लयि भुगतान करने में सक्षम स्थापति अभकिर्त्ताओं की तुलना में स्टार्टअप अधिक नुकसान में होंगे ।
 - एक खुले और वविधि पारस्थितिकि तंत्र के निर्माण की बजाय इसका परिणाम एक ऐसे वेब के रूप में हो सकता है जिसमें सीमति संख्या में शक्तिशाली संस्थाओं का वर्चस्व हो ।

■ उपभोक्ताओं के लिये पैकेज प्लान:

- नेट न्यूट्रैलिटी की कमी से सुविधाओं तक नःशुल्क पहुँच के बजाय उपभोक्ताओं के लिये "पैकेज प्लान" की व्यवस्था हो सकती है।
- उदाहरण के लिये उपयोगकर्ताओं को अपने देश में स्थिति वेबसाइट्स की तुलना में अंतरराष्ट्रीय वेबसाइट्स का उपयोग करने के लिये अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। इससे एक सतरीय इंटरनेट प्रणाली का नरिमाण हो सकता है जिसमें अधिक भुगतान करने वाले उपयोगकर्ताओं को सामग्री तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा/से भारत सरकार का/के "डजिटल इंडिया" योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

1. भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा की चीन ने कया।
2. एक नीतगित ढाँचे की स्थापना जिससे बड़े आँकड़े एकत्रति करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा दया जा सके कविे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के भीतर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।
3. हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से वदियालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटन केंद्रों में वाई-फाई लाना।

नीचे दये गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनयै :

- केवल 1 और 2
केवल 3
केवल 2 और 3
1, 2 और 3

उत्तर: (b)

[स्रोत: द हद्दि](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/net-neutrality-2>

